वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - I)
2019-20

सिडबी

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

सुदृढ़ एमएसएमई से परिपूर्ण ऊर्जावान अर्थव्यवस्था के लिए

सिडबी विज़न 2.0

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए, निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से उत्प्रेरक और सुगमकार की भूमिका निभाना :

1. नीतिगत पक्षपोषण
2. ऋण संस्थाओं के बीच समन्वय
3. संगठित प्रयासों के माध्यम से संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ
4. नीति-निर्माताओं और ऋणदात्री संस्थाओं को आँकड़ों और अनुसंधान पर आधारित प्रासंगिक निर्णायक बिंदु उपलब्ध कराना
5. नवयुगीन प्रौद्योगिकियाँ अपनाने वाले नए एवं नवोन्मेषी मॉडलों के माध्यम से ऋण का प्रवाह सुगम बनाने के लिए, ऋण संस्थाओं की ओर से संस्थागत तंत्र का विकास करना
6. सरकार, विनियामकों, स्टार्टअप, निधीयन एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं के व्यापक पारितंत्र के साथ मिलकर काम करते हुए, राष्ट्र के युवाओं के बीच उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रमों / गतिविधियों का संचालन

हमारी रिपोर्ट ऑनलाइन देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें :
www.sidbi.in

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

एमएसएमई आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण कर्णधार हैं और ये स्वस्थ एवं समृद्ध समुदायों के निर्माण के लिए अत्यावश्यक हैं। इस क्षेत्र की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होने के नाते, बैंक इस क्षेत्र को वित्तपोषण, संवर्द्धन, विकास और हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के संदर्भ में दिए जा रहे अपने सहयोग में सुदृढ़ता ला रहा है, ताकि जिस पारितंत्र में एमएसएमई काम करते हैं, उसे सुदृढ़ अंतर्निहित पारितंत्र बनाया जा सके। कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय की माँग है कि एमएसएमई की सहायता के लिए सभी हितधारक अधिक सहयोगपरक दृष्टिकोण अपनाएँ।

प्रेषण पत्र

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

20 जुलाई, 2020

महोदय,

सिडबी के वित्तवर्ष 2019-20 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतदद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

(1) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति; तथा

(2) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट।

भवदीय,

(मोहम्मद मुस्तफा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक : यथोक्त

सिडबी का निदेशक मंडल
(यथा 31 जुलाई, 2020)

श्री मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

श्री वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

श्री पंकज जैन

श्री जी.के. कंसल

श्री वी. सत्य कुमार

श्री एल.आर. रामचंद्रन

श्री जी. गोपालकृष्ण

श्री आशीष गुप्ता

श्रीमती नूपुर गर्ग

विव 2020 के दौरान निदेशक मंडल की पाँच बैठक हुईं।

सिडबी

बोर्ड स्तर की समितियों का विवरण
(यथा 31 जुलाई, 2020)

कार्यकारिणी समिति (6 बैठकें)*

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

जोखिम प्रबंध समिति
(6 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (3 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पुष्पिंदर सिंह (बाहरी विशेषज्ञ)

मानव संसाधन संचालन समिति

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 डॉ. चित्रा राव (बाहरी विशेषज्ञ)

उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति
(5 बैठकें)

1 श्री मनोज मित्तल, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री जी.के. कंसल
4 श्री वी. सत्य कुमार
5 श्रीमती नूपुर गर्ग

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

1 श्री पंकज जैन

लेखापरीक्षा समिति (4 बैठकें)

1 श्री वी. सत्य कुमार, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री आशीष गुप्ता

उच्च राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति (3 बैठकें)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री जी.के. कंसल
6 श्री वी. सत्य कुमार

ग्राहक सेवा समिति (1 बैठक)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री जी.के. कंसल
5 श्री वी. सत्य कुमार

वसूली समीक्षा समिति (2 बैठकें)

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री मनोज मित्तल
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव
4 श्री पंकज जैन
5 श्री गोपालकृष्ण

इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

1 श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष
2 श्री आशीष गुप्ता

संवर्द्धन एवं विकास गतिविधियों हेतु समिति (1 बैठक)

1 श्री देवेंद्र कुमार सिंह
2 श्री पंकज जैन
3 श्री वी. सत्य वेंकट राव

* कोष्ठक में दी गई संख्या वित्त वर्ष 2020 के दौरान संबंधित समिति की बैठकें दर्शाती हैं।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

एआईएफ़ – वैकल्पिक निवेश निधि

एएलएम – आस्ति देयता प्रबंध

ऐस्पायर – नवोन्मेषिता और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक योजना

बीसीएम – व्यवसाय निरंतरता प्रबंध

सीएफ़सी – सामूहिक सुविधा केंद्र

सीएलसीएसएस – ऋण-संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना

सीपीएसयू – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

सीआरएमएस – ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली

सीआरआर – आरक्षित नक़दी निधि अनुपात

सीएससी – सामूहिक सेवा केंद्र

सीएसओसी – साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र

सीटीईओ – मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन

सीटीएफ़ – स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि

सीवीपीसी – केंद्रीय विक्रेता भुगतान कक्ष

डीसीएस – प्रत्यक्ष ऋण योजना

डीएफ़आईडी – डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट

डीएफ़एस – वित्तीय सेवा विभाग

डीआईसीजीसीआई – दलित इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

डीपीआईआईटी – उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग

ईईएसएल – एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

ईएलएससी – त्वरित ऋण सेवा केंद्र

ईपीएफ़ – कर्मचारी भविष्य निधि

ईएससीओ – ऊर्जा सेवा कंपनियाँ

एफ़पीटीयूएफ़एस – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

जीसीएफ़ – ग्रीन क्लाइमेट फंड

जीईएफ़ – ग्लोबल एन्वायरनमेंट फ़ैसिलिटी

एचएफसी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ

आईसीएएपी – आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया

आईडीएलएसएस – एकीकृत चमड़ा क्षेत्र विकास योजना

आईएमएफ़ – अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

आईआरएमएस – एकीकृत जोखिम प्रबंध प्रणाली

लिक्विड – प्रत्यक्ष वित्त के माध्यम से निधियों का तत्काल आधान करते हुए चलनिधि सहायता

एमडीपी – प्रबंध विकास कार्यक्रम

एमएफ़आई – अल्पवित्त संस्था

एमएसई – सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसई-सीडीपी – सूक्ष्म और लघु उद्यम – उद्यम-समूह विकास कार्यक्रम

एमएसएफ़ – सीमांत स्थायी सुविधा

एमएसएमई – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

एनबीएफ़सी – गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी

एनईआर – उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

एनआईएम – निवल ब्याज मार्जिन

एनएलएससी – राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति

एनएसडीसी – राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

ओईएम – मूल उपकरण विनिर्माता

ओआरएम – परिचालनगत जोखिम प्रबंध

पीएलआई – प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ

पीएमजीकेपी – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज़

पीएमकेके – प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

पीएमकेवीवाई – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पीएसबी – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

आरएफ़एस – प्राप्य वित्त योजना

आरओए – आस्तियों पर प्रतिफल

आरओसीई – प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिफल

आरओई – ईक्विटी पर आय

आरआरसी – वसूली समीक्षा समिति

आरसेटी – ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

सेफ़ – कोरोना वायरस के विरुद्ध आपातकालीन कार्रवाई के लिए सिडबी की सहायता

एसएआरबी – विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा

एसडी-वैन – सॉफ्टवेयर संचालित वाइड एरिया नेटवर्क

एसएफ़बी – लघु वित्त बैंक

एसएमए – विशेष उल्लेखनीय खाता

स्मार्ट – सिडबी मल्टीफंक्शनल मूल्यांकन और रेटिंग टूल

स्माइल – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी मेक इन इंडिया सुलभ ऋण निधि

स्विफ्ट – सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन

टीएटी – टर्न अराउंड टाइम

टेक्अप – प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन

टीएलटीआरओ – लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन

ट्रेड्स – ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

टीआरएमवी – कोषागार एवं संसाधन प्रबंध उद्-भाग

टीयूएफएस – प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

त्वरित – कोरोना संकट के समय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समय पर कार्यशील पूँजी सहायता

वीसीएफ़ – वेंचर कैपिटल फंड

डब्ल्यूसीटीएल – कार्यशील पूँजी सावधि ऋण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

"बैंक इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एमएसएमई के साथ गहराई से संलग्न होगा। बैंक की दृष्टि और पहल एमएसएमई को सशक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ हमेशा संरेखित रहेगी और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

विगत वर्ष

एमएसएमई की सहायता सम्बन्धी अपने प्रयासों में बैंक ने नयी ऊंचाइयों को छुआ। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि विज़न 2.0 के साथ रूपान्तरण की जो यात्रा हमने आरम्भ की थी, वह परिचालन के धरातल पर फलीभूत होने लगी है और एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण, संवर्द्धन एवं विकास तथा उसकी गतिविधियों के समन्वयन संबंधी हमारी भूमिका में नये आयाम जुड़े हैं। वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रहीं-

- वित्त वर्ष 2020 के अंत में आस्ति-आधार में वर्षानुवर्ष 20.3% की वृद्धि दर्ज़ हुई और वह ऊपर उठने की वित्त वर्ष 2018 व 2019 की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए ₹1,87,539 करोड़ (वित्त वर्ष 2019 में ₹1,55,861 करोड़) की नयी ऊँचाई पर जा पहुँचा।
- ऋण और अग्रिम में 21.4% की वृद्धि हुई और वे वित्त वर्ष 2020 के अंत में ₹1,65,422 करोड़ रहे।
- बैंक की कुल आय में 21.9% की वृद्धि हुई और वह ₹12,090 करोड़ रही। निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वित्त वर्ष 2020 में उल्लेखनीय रूप से 27.9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 23% रही थी।
- बैंक ने निवल ब्याजान्तर में भी 5 आधार बिन्दुओं का सुधार किया, जो वित्त वर्ष 2019 के 1.89% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 1.94% हो गया, जबकि लागत-आय अनुपात, वित्त वर्ष 2019 के 17% से घट कर वित्त वर्ष 2020 में 14% हो गया।
- निवल लाभ ने वृद्धि जारी रखते हुए एक नया कीर्तिमान रचा। वित्त वर्ष 2020 में 18.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज़ करते हुए बैंक ने ₹2,314.5 करोड़ का अब तक का अपना अधिकतम निवल लाभ अर्जित किया।
- शेयरधारकों के प्रतिलाभ में सुधार हुआ है। ईक्विटी पर प्रतिलाभ, नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ और प्रति शेयर अर्जन पिछले वर्ष के क्रमशः 12.59%, 12.57% तथा ₹36.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में क्रमशः 13.19%, 12.83% और ₹43.5 हो गये।

संवृद्धि के स्तंभ

वित्त वर्ष 2020 के दौरान संस्थागत वित्त-बही ने ₹1.5 लाख करोड़ के पड़ाव को पार किया और वर्षानुवर्ष 22.6% की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹1,55,429 करोड़ पर पहुँच गयी। एमएसई को ऋण की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों व लघु वित्त बैंकों को ₹94,798 करोड़ का संवितरण किया। बैंकों और लघु वित्त बैंकों के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी अल्पसेवित घटकों और भू-भागों को ऋण प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की तरलता सम्बन्धी चिन्ताओं के समाधान के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में ₹3,650 करोड़ संवितरित किए, जिसके फलस्वरूप गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कुल बकाया वर्षानुवर्ष 10.7% बढ़कर ₹10,375 करोड़ हो गया। एमएसएमई ऋण-जगत में नये युग की फिनटेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरीं है और उनकी संभावित पहुँच को देखते हुए, बैंक ने नये युग की फिनटेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रायोगिक तौर पर एक नयी योजना

आरम्भ की है तथा 10 फिनटेक को उससे जोड़ा है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 में कुल ₹75 करोड़ का संवितरण किया गया।

प्रत्यक्ष वित्त परिचालनों को बल देने के उद्देश्य से बैंक ने त्वरित ऋण सेवा केन्द्र (ईएलएससी) तथा विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा (सार्ब) नामक नये ऋण-प्रदायगी मॉडल लागू किए, ताकि प्रभावोत्पादकता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी दृष्टिकोण पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। साथ ही, किफायती ब्याज-दरों पर तेजी से ऋण-प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान 13 नये गैर-स्माइल उत्पाद आरम्भ किए। प्रभावशाली ऋण-प्रदायगी मॉडल और इन उत्पादों के सम्मिलित परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष ऋण बकाया में 10.9% की वृद्धि हुई हैं, जबकि ग्राहक-आधार 26.8% बढ़ा है।

एमएसएमई को सुचारु रूप से ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बैंक ने पिरामिड की तलहटी पर विद्यमान सूक्ष्म उद्यमियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। 'प्रयास' योजना के माध्यम से बैंक इन उद्यमियों तक पहुंचा और साझेदारियों के ज़रिए 14,000 सूक्ष्म उद्यमियों को ₹161.11 करोड़ के ऋण मंजूर किए।

स्टार्ट-अप पारितंत्र की सहायता के लिए भारत सरकार के प्रायोजन वाली निधियों की निधि के अंतर्गत बैंक ने अपने परिचालनों को बढ़ाया है। निधियों की निधि परिचालनों के ज़रिए बैंक ने विभिन्न निधियों के अंतर्गत 140 वैकल्पिक निवेश निधियों को सहायता दी है। यथा 31 मार्च 2020 इसके अंतर्गत ₹6,154.71 करोड़ की संचयी मंजूरियाँ और ₹2,848.13 करोड़ के संवितरण हुए थे। निधियों की निधि के अंतर्गत संवितरण के परिणामस्वरूप 338 स्टार्ट-अप्स तथा 158 संवृद्धि कंपनियों में कुल ₹3,582 करोड़ के निवेश हुए।

स्टार्टअप्स के लिए निवेश तक पहुँच को सुगम बनाने के प्रयासों के क्रम में बैंक ने द्वितीय निवेशक-दिवस मनाया, ताकि सभी हितधारकों को साथ लाया जा सके। खुशी की बात है कि 2 निवेशक-दिवस कार्यक्रमों में चुने गये 37 स्टार्ट-अप्स में से 31 के लिए वीसी/पीई ने रुचि दर्शायी। आनेवाले वर्षों में इन प्रयासों में बढ़ोत्तरी करने के लिए बैंक एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इसमें पूरी दुनिया के 500 से अधिक स्टार्टअप्स और वैकल्पिक निवेश निधियों तथा उद्यम पूँजी विशेषज्ञों के सम्मिलित होने की संभावना है।

एमएसएमई पर प्रभाव

- विगत वर्षों में बैंक के प्रयासों से ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, ऋण-लागत में कमी, एमएसएमई को डिजिटल प्लैटफॉर्मों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उभरते हुए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एमएसएमई क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला गया है।

- यथा मार्च 2020 बैंक का संस्थागत वित्त देश के कुल एमएसई बकाया का 13.5% रहा। वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों को संवितरित किए गए ₹94,798 करोड़ से 14.17 लाख एमएसई को लाभ हुआ, जिससे 15.18 लाख रोजगार पैदा हुए। उक्त संवितरण में से ₹3,444 करोड़ बैंकों को 109 आकांक्षी जिलों में सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित किए गए, इससे 1.52 लाख रोजगार पैदा हुए। इसके अलावा, ₹25,184 करोड़ बैंकों को 453 पिछड़े जिलों में सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित किए गए, इससे 7.36 लाख रोजगार पैदा हुए।

- बैंक ने बड़ी संख्या में एमएसएमई के लिए आवश्यकतानुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों का लगातार नवोन्नयन किया और 31 मार्च 2020 तक अपना ग्राहक-आधार बढ़ाकर 6,595 तक पहुँचा दिया। संवर्द्धन और विकास गतिविधियों के अंतर्गत बैंक 30 पहलकदमियों के माध्यम से, 5 लाख लाभग्राहियों तक पहुँचा है जो विशेषतः गरीब राज्यों से हैं।

कोविड 19 वैश्विक महामारी और एमएसएमई

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद और समग्र निर्यात में क्रमशः लगभग 30% और 50% का योगदान करते हैं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने के भारत के सपने को साकार करने में एमएसएमई की प्रमुख भूमिका रहेगी। हालांकि कोविड 19 महामारी ने एमएसएमई और खासकर लघु व्यवसायों के परिचालनों और उनकी लाभप्रदता की मात्रा को प्रभावित किया है, तथापि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी वापसी और पुनरुज्जीवन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री ने 'आत्म-निर्भर भारत' और 'लोकल के लिए वोकल' का जो लक्ष्य दिया

है, उससे आनेवाले दिनों में एमएसएमई उत्पादों के राष्ट्रीय और वैश्विक ब्राण्डों के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, एमएसएमई की परिभाषा में किए गए बदलाव से मझोले आकार की सेवा-क्षेत्र इकाइयाँ इस क्षेत्र में शामिल हो जाएंगी, जिससे एकल उद्यम के स्तर पर एमएसएमई के ऊर्ध्वमुखी विकास में बहुत मदद मिलेगी।

कोविड 19 के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए भारत सरकार के बहुत-से प्रयासों के क्रियान्वयन के मामले में बैंक एक विश्वसनीय एजेंसी बना हुआ है। इस संकट-काल में एमएसएमई की मदद के लिए प्रत्यक्ष वित्त, संस्थागत वित्त, निधियों की निधि तथा संवर्द्धन और विकासपरक परिचालनों के ज़रिए बैंक ने कई उपाय किए हैं। बैंक द्वारा समय पर किए गये लक्ष्यबद्ध प्रयासों, जैसे ₹15,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा के अतर्गत बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं को तरलता सहायता, सेफ, सेफ प्लस, त्वरित तथा लिक्विड योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को सहायता और संवर्द्धन और विकासपरक परिचालनों एवं सीएसआर संबंधी गतिविधियों के ज़रिए जीविकोपार्जन के लिए सहायता के ज़रिए इस चुनौतीपूर्ण समय में एमएसएमई की मदद की गयी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, इस योजना के क्रियान्वयन-साझेदार की हैसियत से बैंक लाखों पथ-विक्रेताओं की मदद करने के राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुश है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंक इसके हितधारकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़कर काम करेगा। इसके अलावा, बैंक ने स्वावलंबन संसाधन सुविधा के अंतर्गत स्वावलंबन संकट-समाधान निधि स्थापित की है, ताकि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की लागत / पंजीकरण शुल्क की आंशिक पूर्ति की जा सके और इस प्रकार समाप्तप्राय नकदी-प्रवाह से जूझ रहे एमएसएमई को राहत पहुँचाई जा सके।

संवर्द्धन और विकासपरक पहलकदमियाँ

बैंक ने सम्पर्क, संवाद, सुरक्षा और संप्रेषण शीर्षकों के अंतर्गत बहुत-सी पहलकदमियाँ प्रारंभ की हैं। मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत बैंक ने युवाओं, असेवित/अल्पसेवित घटकों और भौगोलिक क्षेत्रों तथा पिरामिड के निचले स्तर में उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के अधिदेश को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए उद्यमिता संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार किया गया है। शैक्षिक संस्थान वे सर्वोत्तम स्थान हैं, जहाँ उद्यमिता का पथ चुनने के लिए युवाओं का मन आकर्षित किया जा सकता है। युवाओं तक पहुँचने के उद्देश्य से बैंक ने शैक्षिक संस्थानों में 118 स्वावलंबन भित्तियाँ तथा 15 स्वावलंबन क्लब स्थापित किए हैं और आईआईएम, लखनऊ में एमएसई के लिए एक अल्पावधि प्रबन्ध विकास कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक ने पाँच राज्यों में 100 स्वावलंबन कनेक्ट केन्द्र भी स्थापित किए हैं, ताकि आकांक्षी उद्यमियों की प्रोफाइल तैयार की जा सकें और उनकी उद्यमिता-यात्रा में शुरू से अंत तक उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा, बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों, खासकर महिलाओं की मदद के लिए कई प्रयास किए हैं, ताकि वे विकास की अगली छलाँग लगा सकें। 12 शहरों में स्वालम्बन बाज़ारों के माध्यम से बैंक ने 600 से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों को मंच प्रदान किया, ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। साथ ही, उन्हें ऋण और विपणन की सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता, डिजाइन आदि का संतुलित सम्मिश्रण उपलब्ध कराया गया। ऐसी ही अन्य पहलकदमियों में, बैंक ने सिडबी महिला उद्यमी सशक्तीकरण परियोजना (एमयूएसपी) की लाभग्राही महिलाओं के लिए एक स्वावलंबन उत्सव आयोजित किया, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें और नेटवर्किंग के ज़रिए नये आदेश पा सकें। बैंक की योजना है कि स्वावलंबन संकल्प के अंतर्गत डीआईसीसीआई के साथ मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर 30 कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि स्टैण्ड अप इंडिया योजना को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार के निदर्शी संस्थागत उपायों से न केवल पिरामिड के निचले स्तर के सूक्ष्म उद्यमियों को लाभ होता है, बल्कि इनसे हितधारकों को परस्पर मिलने-जुलने और इन प्रयासों को आगे ले जाने का अवसर भी मिलता है।

एमएसएमई पर श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, बैंक ने 10 राज्य सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि एमएसएमई के संबंध में राज्य सरकारों से निकटता से जुड़ा जा सके और डिजिटल मंचों पर सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके। इसे और आगे बढ़ाते हुए, बैंक की योजना है कि अलग-अलग प्रकार के 10 क्लस्टर सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

यह सूचित करते हुए मुझे गर्व है कि स्वावलंबन सिलाई स्कूल की पहल बहुत सफल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 राज्यों के 10 जिलों में 1,000 सिलाई स्कूल स्थापित किए गए। इससे 1,000 ग्रामीण महिलाओं को

'गृह-उद्यमी' बनाकर आगे बढ़ाया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक गृह-उद्यमी ने तीन अन्य महिलाओं को अपने से जोड़ लिया है। इससे कार्यक्रम का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है और मार्च 2020 तक प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 3,273 हो गयी। महामारी की चुनौती का उत्तर देते हुए, इन गृह-उद्यमियों ने अपनी सुदृढ़ता का परिचय दिया और कोविड-योद्धा के रूप में सामने आकर ग्रामीण आबादी को मास्क उपलब्ध कराए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चरण 2 में 700 और सिलाई स्कूल खोलने की योजना है।

सिडबी ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्रचुर प्रतिभागिता वाले अनूठे एमएसई पुरस्कार के रूप में उभरे हैं। इन पुरस्कारों के द्वितीय आयोजन में 13,000 से अधिक पंजीकरण हुए तथा 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजयी रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बैंक के एमडीपी तथा मेंटरशिप कार्यक्रम का लाभ दिया गया।

वैचारिक नेतृत्व

सूचना की विषमता के समाधान हेतु बैंक ने अनेक प्रकार के ज्ञानपरक उत्पादों के माध्यम से कई प्रकार की पहलकदमियाँ की हैं। अपने वर्तमान ज्ञानपरक उत्पादों, जैसे- एमएसएमई पल्स और क्रिसिडेक्स में अतिरिक्त मापदण्ड शामिल करके उन्हें और व्यापक बनाते हुए बैंक ने माइक्रोफाइनेंस पल्स की शुरुआत की, ताकि अल्प वित्त क्षेत्र के हितधारकों के लिए डाटा-युक्त नीतिगत अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई जा सके। एमएसएमई सम्बन्धी भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि ज्ञानपरक उत्पाद स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसके मद्देनज़र एमएसएमई पल्स को अंग्रेजी के साथ-साथ, हिन्दी, मराठी और तमिल में भी उपलब्ध कराया गया है। बैंक अभी कुछ और ज्ञानपरक सामग्री प्रकाशित करने जा रहा है, ताकि नवीनतम आयामों, जैसे फिनटेक ऋण-प्रदायगी तथा प्रमुख उद्योग-क्षेत्रों पर डाटा बिन्दु उपलब्ध कराए जा सकें।

इसके अलावा अल्प वित्त क्षेत्र की सभी संस्थाओं तथा हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने के उद्देश्य से बैंक ने द्वितीय सिडबी नेशनल माइक्रोफाइनेंस कांग्रेस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन में अल्प वित्त क्षेत्र की उभरती हुई चुनौतियों, संभावित रणनीतियों के विकास तथा क्षेत्र की भावी दिशा निर्धारित करने पर विचार किया गया। प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों की उल्लेखनीय प्रतिभागिता रही। आगे भी हम इस प्रकार के प्रयास जारी रखेंगे।

समूह की कंपनियों का योगदान

बैंक के सहयोगी और सहायक नेटवर्क ने एमएसएमई पारितंत्र के सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है और इस क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की है। सीजीटीएमएसई ने 43.07 लाख एमएसई ऋण-खातों का सृजन किया, जिनकी कुल ऋण-राशि ₹2.21 लाख करोड़ है। मुद्रा ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान ₹4,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की, जिसमें गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी-अल्प वित्त संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का संचालन करता है। यथा 31 मार्च 2020 इसके पास 489 पंजीकृत क्रेताओं, 1,787 एमएसएमई विक्रेताओं तथा 35 वित्त-प्रदाताओं का आधार है। वित्त वर्ष 2020 के अंत तक आरएक्सआईएल प्लेटफॉर्म ने कुल ₹3,816.39 करोड़ के 94,342 बीजकों का वित्तपोषण किया है। एसवीसीएल वर्तमान में आठ निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है जिनकी आहरण-योग्य समूह-निधि ₹1,754.24 करोड़ है। एसवीसीएल ने न्यू होराइज़न फंड (एनएचएफ) स्थापित किया है, और उभरते सितारे फंड स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ऐक्युइट रेटिंग्स ने 31 मार्च 2020 तक 50,000 से अधिक एसएमई तथा 8,000 से अधिक बैंक ऋणों को रेटिंग दी है।

भावी प्रयास-योजना

भविष्य में बैंक एमएसएमई के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़कर काम करेगा, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में क्षेत्र की सहायता की जा सके। बैंक सदैव अपने दृष्टिकोण और प्रयासों को एमएसएमई के सशक्तीकरण और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखेगा। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दे रहा है, ताकि आनेवाले समय में इसकी कार्य-शक्ति एमएसएमई की और प्रभावी तरीके से सेवा कर सके।

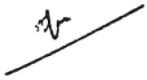

मोहम्मद मुस्तफ़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक रिपोर्ट

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

(वी. सत्य वेंकट राव)
उप प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए आपके बैंक के समग्र व्यवसाय और परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, बैंक का निदेशक मण्डल प्रसन्नता व्यक्त करता है।

बैंक के विज़न 2.0 के तहत रूपांतरण रणनीति से परिचालन के साथ-साथ वित्तीय मोर्चों पर उत्साहवर्द्धक प्रतिफल प्राप्त होने लगे हैं। वित्तवर्ष 2019 में सफल रहने के बाद, बैंक ने इस वित्तवर्ष में भी तेजी से नई उपलब्धियां हासिल की है। बैंक संस्थागत ऋण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और नए ऋण वितरण मॉडल की शुरुआत, उत्पाद समूहों को वृहत करने और प्रत्यक्ष ऋण परिचालन में त्वरित ऋण वितरण सुनिश्चित करके अंतिम-स्तर तक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में प्रभावी रहा है।

विज़न 2.0 के अनुरूप, बैंक ने सूचना की असमानता को दूर करने और डिजिटल हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अभिनव और गैर परम्परागत पहलों के माध्यम से वैचारिक नेतृत्व, सुगमकर्ता (फ़ैसिलिटेटर) और समूहक (एग्रीगेटर) की भूमिका निभाई है। बैंक के प्रयासों को यथोचित सराहना मिली है, और बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए "बिजनेस एक्सीलेंस फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट" के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका बैंक जनसमूह, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और वित्त के मुख्य सक्षमकर्ताओं के माध्यम से अपने सभी आधार स्तंभों, यथा, संस्थागत वित्त, प्रत्यक्ष ऋण, संवर्द्धन एवं विकासात्मक पहल, सहायक नेटवर्क, एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म और निधियों की निधि को निरंतर सुदृढ़ करता रहेगा, ताकि सभी संकेन्द्रित क्षेत्रों में, पूर्ण रूपांतरण कर सके।

वित्तवर्ष 2020 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अगले अध्यायों में विस्तार से बताया गया है।

(मनोज मित्तल)
उप प्रबंध निदेशक

(वी. सत्य वेंकट राव)
उप प्रबंध निदेशक

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिन्दु भाग- I में दर्शाए गए हैं और वित्तवर्ष 2020 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भाग-II में संलग्न हैं।

प्रगति का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च	1991	2016	2017	2018	2019	2020
कुल आस्तियाँ	5,309.19	76,478.47	79,682.33	1,08,869.45	1,55,860.83	1,87,538.98
बकाया संविभाग	5,176.8	65,632.1	68,289.6	95,290.7	1,36,230.37	1,65,421.56
पूँजी - अधिकृत	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
- प्रदत	450.0	487.0	531.92	531.92	531.92	531.92
आरक्षितियाँ एवं निधियाँ	44.9	11,108.3	13,069.5	14,359.98	16,153.16	18,465.54
कुल आय (प्रावधान पश्चात)	425.1	5,559.5	6,266.5	6,556	9,919	11,137.32
निवल लाभ	35.6	1,177.5	1,120.2	1,429.2	1,952.21	2,314.52
शेयरधारकों को लाभांश	5.0	94.7	93.9	137.7	165.12	0
औसत बकाया संविभाग पर प्रतिलाभ (%)	0.7	2.9	2.5	2.56	2.06	1.89
निवल बकाया संविभाग के प्रतिशत के रूप में मानक आस्तियाँ	100	99.27	99.56	99.74	99.79	99.60
पूँजी व जोखिम आस्ति का अनुपात (%)	13.9	29.86	28.42	26.73	27.11	26.62

वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़)

विवरण	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2019	बकाया राशि यथा 31 मार्च, 2020
I. अप्रत्यक्ष ऋण		
क. बैंकों, लघु वित्त बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त	1,16,277	1,43,233
ख. अल्पवित्त संस्थाओं को सहायता	1,172	1,821
ग. गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को सहायता	9,370	10,375
कुल अप्रत्यक्ष ऋण	**1,26,819**	**1,55,429**
II. प्रत्यक्ष ऋण		
क. ऋण और अग्रिम	8,897	9,867
ख. प्राप्य वित्त योजना एवं बिल भुनाई	514	126
कुल प्रत्यक्ष ऋण	**9,411**	**9,993**
सकल योग	**1,36,230**	**1,65,422**

अध्याय 1 ▸ एमएसएमई परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक[1] और आईएमएफ़[2] ने कोविड महामारी के कारण कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रमश: 5.2% और 3% के संकुचन का अनुमान लगाया।

विश्व बैंक और आईएमएफ़ कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए आशावादी बने हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उनका क्रमशः 4.2% और 5.8% की वृद्धि का अनुमान है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वित्तवर्ष 2020 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.2% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 6.1% थी।

व्यापार के मोर्चे पर, वित्तवर्ष 2020 के दौरान रुपये के संदर्भ में निर्यात में 3.52% एवं आयात में 7.98% की गिरावट आई और मार्च 2020[4] में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन को किए गए निर्यातों में क्रमशः 19.35% और 32.21% की कमी आई।

वित्तवर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान, आर्थिक गतिविधियों का स्तर कम रहा और मार्च एवं अप्रैल 2020 में निर्यात में क्रमश: 29.98% एवं 56.39% की कमी आई। आयात में भी मार्च और अप्रैल, 2020 में क्रमशः 23.72% और 54.59% की कमी आई[4]।

एमएसएमई का वर्तमान

63 मिलियन
एमएसएमई

110 मिलियन
लोगों को रोज़गार प्रदान करता है

वित्तवर्ष 2019[5] के दौरान **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद** में
30.3%
का योगदान

वित्तवर्ष 2020 की पहली तीन तिमाहियों (दिसंबर 2019 तक) में **अखिल भारतीय निर्यात** में
49.81%[6]
का योगदान।

कुल बिक्री (टर्नओवर) के अतिरिक्त मानदंड और निवेश सीमा में वद्धि के साथ एमएसएमई की परिभाषा पुनरीक्षित की गई। इसके अलावा, विनिर्माण और सेवाक्षेत्र के बीच का विभेद समाप्त कर दिया गया। पुनरीक्षित परिभाषा में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए कुल कारोबार में निर्यात शामिल नहीं किया जाएगा।

एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पुनरीक्षित मानदंड[7] नीचे दिए गए हैं :

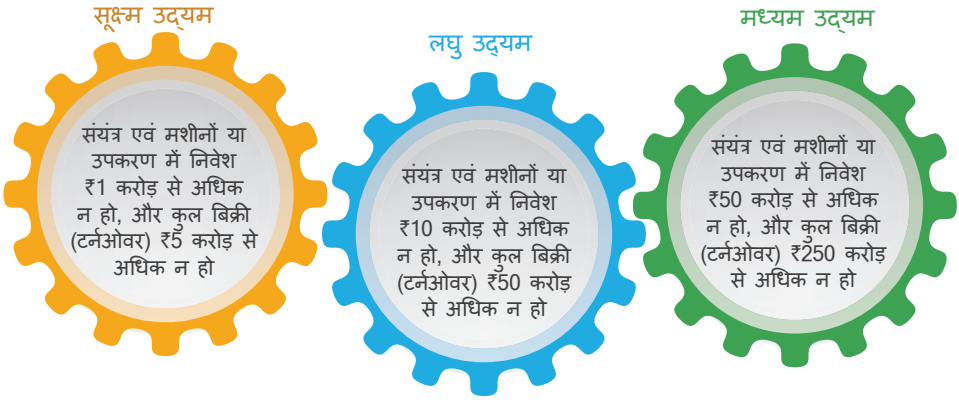

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई पल्स रिपोर्ट - अप्रैल 2020 के अनुसार, जनवरी 2020 तक एमएसएमई को प्रदत्त ऋण (₹50 करोड़ तक के ऋण) ₹17.75 लाख करोड़ थे।

एमएसएमई ऋण जोखिम-सीमा
(₹ लाख करोड़)

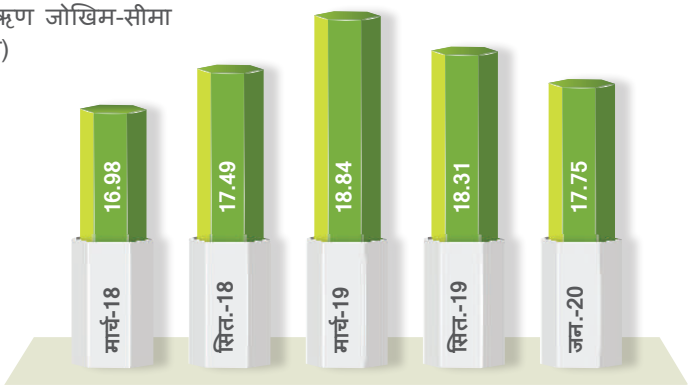

[1] ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जून 2020
[2] वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2020
[3] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
[4] भारतीय विदेश व्यापार - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
[5] मार्च 12, 2020 को संसद में दिया गया जवाब
[6] मार्च 19, 2020 को संसद में दिया गया जवाब
[7] एमओएमएसएमई अधिसूचना - 01, जून 2020

एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और राहत के उपाय

कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई की मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत के उपाय -

सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास[8] निम्नवत् हैं :

01 एमएसएमई सहित व्यवसाय-इकाइयों के लिए ₹3 लाख करोड़ के संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त स्वचालित ऋण, जिनसे लगभग 45 लाख एमएसएमई के लाभान्वित होने का अनुमान है

02 दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए ₹20,000 करोड़ के गौण ऋण, जिसका लक्ष्य लगभग 2 लाख एमएसएमई को लाभान्वित करना है

03 ₹10,000 करोड़ समूहनिधि (कॉर्पस) वाली निधियों की निधि (फ़ंड ऑफ फ़ंड्स) के माध्यम से एमएसएमई में ₹50,000 करोड़ की ईक्विटी का आधान

04 मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सहयोग करने के लिए, ₹200 करोड़ तक की निविदाएँ वैश्विक स्तर की नहीं होंगी

05 पीएमजीकेपी के तहत, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए 6 माह (मार्च-अगस्त 2020) की ईपीएफ़ सहायता के प्रति ₹2,500 करोड़ का प्रावधान

06 जो श्रमिक पीएमजीकेपी के लिए पात्र नहीं हैं, उनके संबंध में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ अंशदान का भार कम करने के प्रति ₹6,750 करोड़ चलनिधि सहायता

07 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूँजी की सुविधा प्रदान करने के लिए ₹5,000 करोड़

08 एमएसएमई क्षेत्र में भौतिक व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर / उनके स्थान पर ई-बाज़ार संबंधी संपर्क को बढ़ावा देना

चलनिधि और विनियामक सहायता सुनिश्चित करने के लिए भा.रि.बैंक के उपाय[8]

- सावधि ऋण किस्तों और कार्यशील पूँजी ब्याज के लिए 31 अगस्त, 2020 तक छह माह की अवधि का ऋण-स्थगन
- नई चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए सीआरआर में कमी और सस्ता ऋण सुनिश्चित करने के लिए रेपो दर में कमी
- चलनिधि बढ़ाने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ के टीएलटीआरओ
- एमएसएफ़ के तहत उधार लेने के लिए बैंक की सीमा में वृद्धि
- नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के माध्यम से ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा
- कार्यशील पूँजी संबंधी वित्तपोषण में सुगमता के लिए मार्जिन में कमी

चैंपियन पोर्टल

- प्रौद्योगिकी-संचालित नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंध सूचना प्रणाली एमएसएमई के लिए सर्व-सेवा स्थल (वन-स्टॉप) रूपी समाधान है
- वैश्विक चैंपियन के रूप में बड़े स्तर पर पहुँचने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना, सहयोग करना और उनकी हैंडहोल्डिंग करना
- भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल के साथ पूर्णत: एकीकृत

एमएसएमई दृष्टिकोण

कोविड महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने के बावजूद, एमएसएमई क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास की संभावनाएँ सकारात्मक बनी हुई हैं। जो तथ्य/मापदंड इस आशा का समर्थन करते हैं, वे हैं :

ऋणों का लाभ उठाने और चलनिधि स्थिति के संदर्भ में, एमएसएमई ऋण के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 3 में से लगभग 2 एमएसएमई लॉकडाउन की अवधि से उबरने के लिए अच्छी स्थित में हैं और 30% की स्थिति बहुत सुदृढ़ हैं[9]

राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न राहत उपायों, नीतियों और कार्यक्रमों का लक्ष्य एमएसएमई के स्तरीय विकास को प्रोत्साहित करना है

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, कुल ₹3.7 लाख करोड़[10] के प्रोत्साहन पैकेज़ से एमएसएमई की तेजी से बहाली हो सकेगी। इस पैकेज़ में ₹3 लाख करोड़ के संपार्श्विक प्रतिभूति-मुक्त ऋण, ₹20,000 करोड़ के गौण ऋण तथा निधियों की निधि के माध्यम से ₹50,000 करोड़ के ईक्विटी-आधान शामिल हैं।

इसके आगे, भारत सरकार के सुधारी उपायों से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की बहाली और पुनरुद्धार में तेजी आने की उम्मीद है। भारत में निर्मित उत्पादों को और बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में शुरू "वोकल फॉर लोकल" पहल से इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

[8] https://champions.gov.in/
[9] एमएसएमई पल्स अप्रैल 2020
[10] https://champions.gov.in/

अध्याय 2 ▸ व्यवसायिक पहलकदमियाँ और समग्र परिचालन

वित्तीय कार्य-निष्पादन

तुलन-पत्र मेट्रिक्स

आस्ति आधार में वर्षानुवर्ष आधार पर 20.3% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि ऋण और अग्रिमों ने ₹1.5 लाख करोड़ के लक्ष्य-स्तर को पार कर लिया

(₹ करोड़)

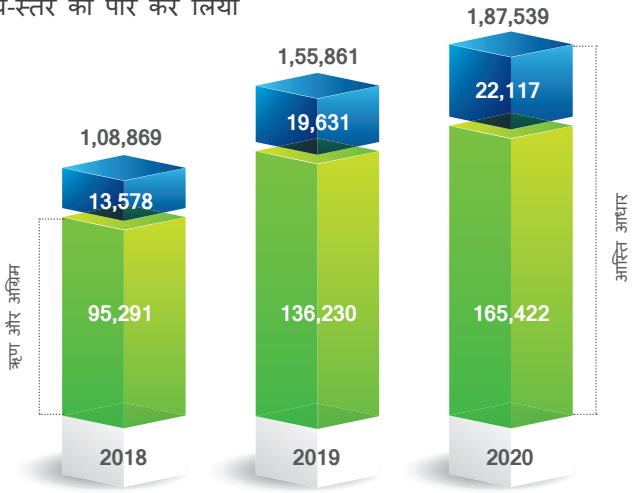

लाभ-हानि मेट्रिक्स

कुल आय में वर्षानुवर्ष 21.9% की वृद्धि दर्ज़ हुई, जबकि निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 27.9% की वृद्धि हुई

(₹ करोड़)

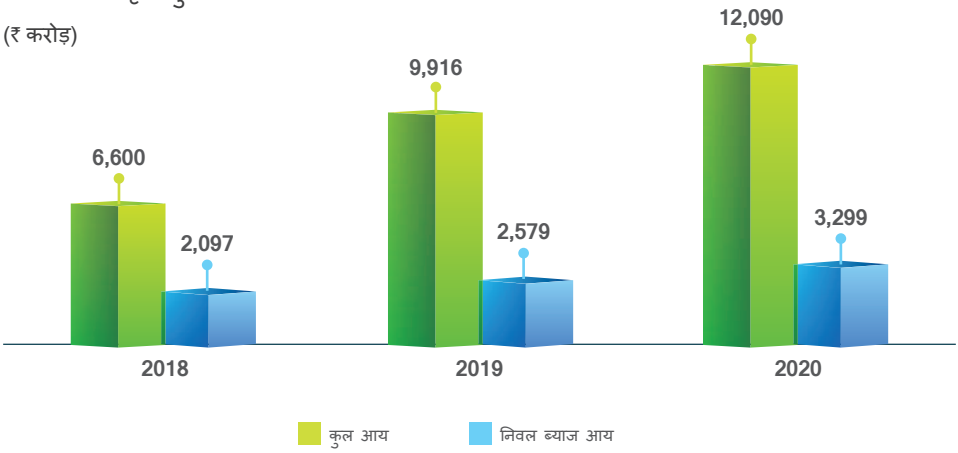

निवल लाभ

वित्त वर्ष 2020 में निवल लाभ में 18.6% की वृद्धि दर्ज़ हुई और वह ₹2,314.5 के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा

(₹ करोड़)

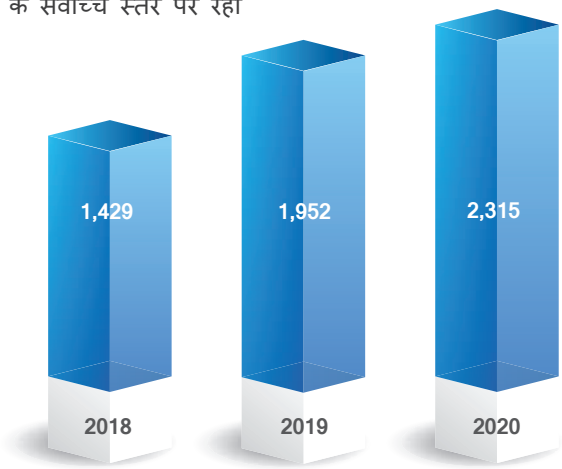

दक्षता मेट्रिक्स

वित्त वर्ष 2020 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 5 आधार बिन्दुओं की वृद्धि हुई और लागत-आय अनुपात में 300 आधार बिन्दुओं के सुधार के साथ यह 14% हो गया है

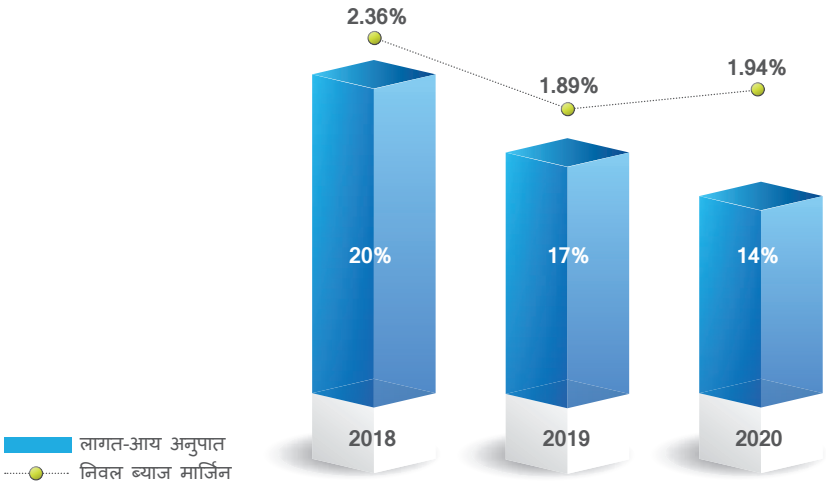

शेयरधारक-प्रतिलाभ मेट्रिक्स

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्त वर्ष 2019 के ₹36.7 से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में ₹43.5 हो गया।

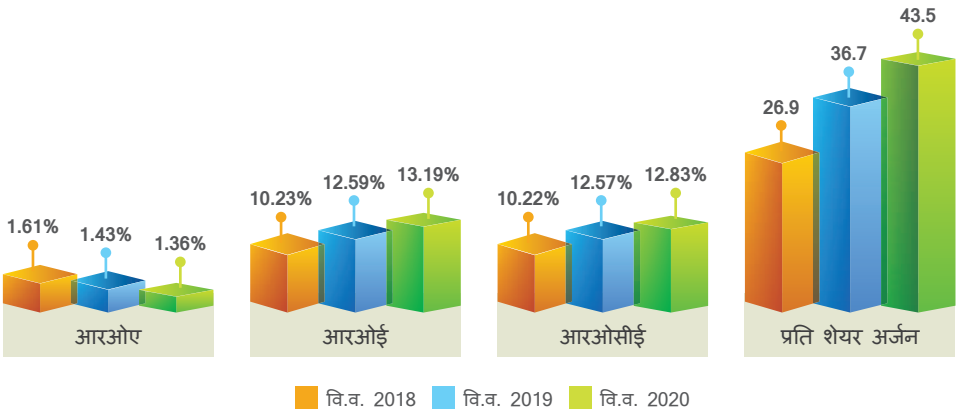

आस्ति गुणवत्ता

वित्त वर्ष 2020 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 0.63% रहा।

यथा मार्च 2020, निवल अनर्जक आस्ति अनुपात वर्षानुवर्ष 19 बीपीएस बढ़कर 0.21% से 0.40% हो गया।

तुलन-पत्र की सुदृढ़ता

मार्च 2019 तक के 87% की तुलना में मार्च 2020 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 78% रहा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2019 के 27.11% की तुलना में मार्च 2020 में 26.62% रहा।

संसाधन प्रबंध

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹78,394 करोड़ संसाधन जुटाए गए, जबकि 2018-19 के दौरान ₹84,483 करोड़ संसाधन जुटाए गए थे।

व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

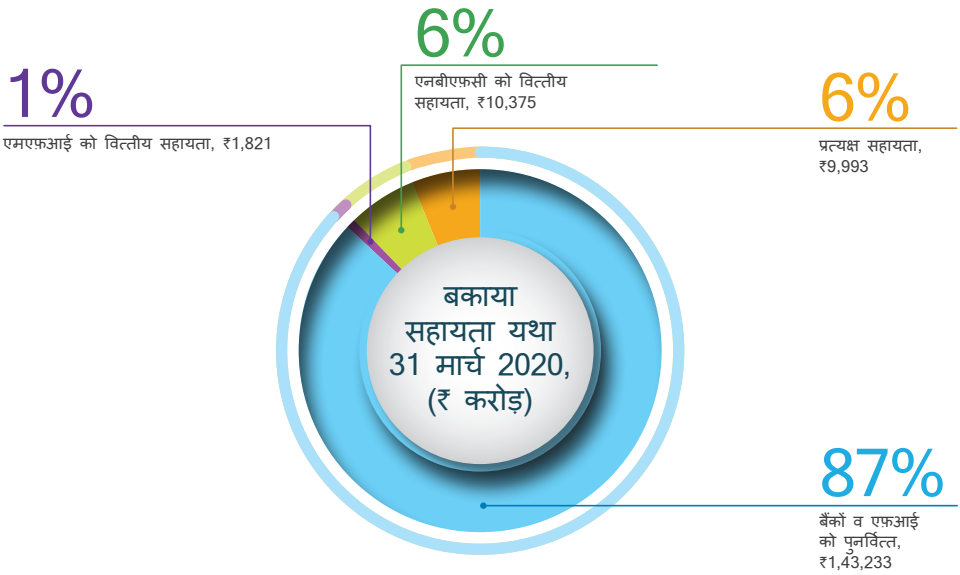

संस्थागत वित्त

बैंक की संस्थागत वित्त आस्ति बही ने ₹1.5 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आँकड़ा पार किया और 22.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2020 तक यह ₹1,55,429 करोड़ पर पहुँच गया।

(₹ करोड़)

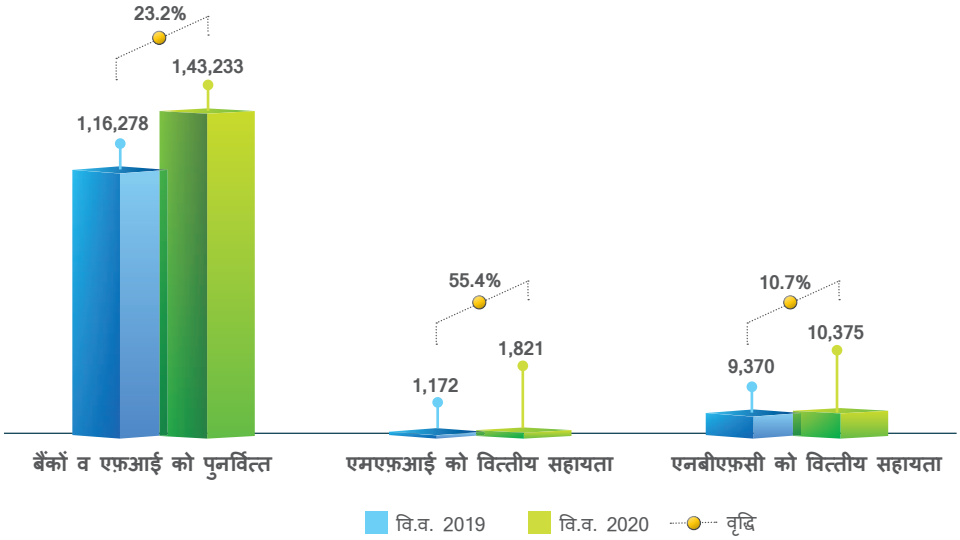

संस्थागत वित्त परिचालन

- वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंकों और एसएफ़बी को ₹94,798 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे 14.17 लाख एमएसई इकाइयाँ लाभान्वित हुई और 15.18 लाख रोज़गार सृजित हुआ

- वर्ष के दौरान एनबीएफ़सी को किए गए संवितरणों की राशि ₹3,650 करोड़ रही
- वर्ष के दौरान एमएफ़आई को किए गए संवितरणों की राशि ₹1,093 करोड़ रही

कोविड का प्रतिकार

एमएसएमई को तरलता सुविधा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष तरलता निधि सुविधा (एसएलएफ़)

- कोविड वैश्विक महामारी के दौरान बैंकों, एनबीएफ़सी और एमएफ़आई के माध्यम से एमएसएमई की सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹15,000 करोड़ की विशेष तरलता निधि सुविधा प्रदान की।
- यथा 31 जुलाई 2020, 16 बैंकों, 50 एनबीएफ़सी संस्थाओं और 39 अल्प-वित्त संस्थाओं को रेपो-आधारित दरों पर सहायता मंजूर की गयी, ताकि संकट से निपटा जा सके।

एमएसएमई पर प्रभाव - संस्थागत वित्त

- ☑ बाजार में परिचालनरत 44 बैंकों और 30 एनबीएफ़सी को पुनर्वित्त प्रदान किया गया
- ☑ यथा मार्च 2020 सक्रिय एमएफ़आई ग्राहकों की संख्या 60 है
- ☑ मार्च 2020 तक संस्थागत वित्तपोषण का बकाया देश के कुल एमएसई बकाया का 13.5% रहा
- ☑ यथा 31 मार्च 2020, एमएफ़आई की संचयी मंजूरियाँ और संवितरण क्रमश: ₹19,871 करोड़ और ₹17,951 करोड़ रहे
- ☑ अल्प वित्त संस्थाओं को दी गई सहायता से संचयी रूप से लगभग 390 लाख वंचित लोग लाभान्वित हुए, जिनमें अधिकतर महिलाएँ हैं

प्रत्यक्ष ऋण

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई पहलकदमियाँ की गईं, जैसे - (i) नई साझेदारियाँ शुरू करना (ii) नए सरलीकृत उत्पाद शुरू करना, जिनका कार्रवाई अवधि कम है (iii) प्रक्रियाओं का सरलीकरण (iv) उत्पादों / प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण (v) ग्राहक-सम्पर्क में वृद्धि (vi) समष्टिगत कारकों पर समय से कार्रवाई।

शुरू किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष वित्त संविभाग में 10.9% और संवितरण में 19.7% की वृद्धि हुई है।

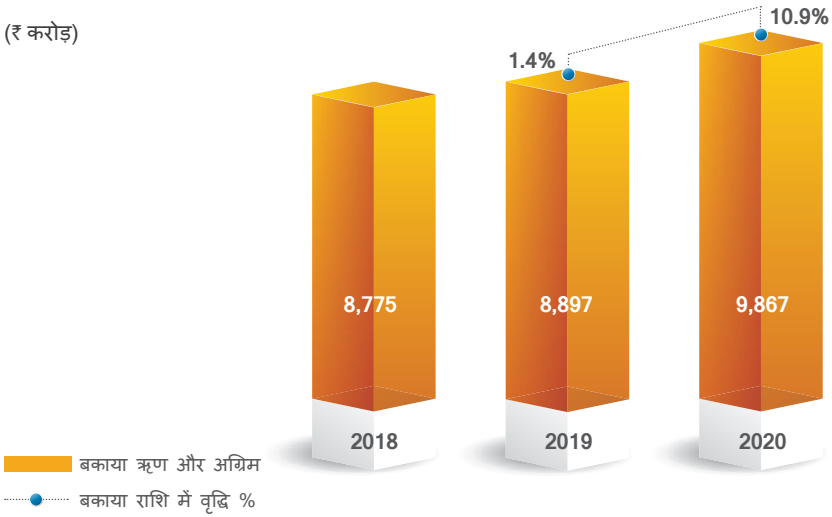

प्रत्यक्ष ऋण व्यवसाय के रणनीतिक पुनरभिमुखीकरण से निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं -

पहुँच का विस्तार

ग्राहकों की संख्या में वर्षानुवर्ष 26.8% की वृद्धि दर्ज की गई

आधार का विविधीकरण

वित्त वर्ष 2020 के दौरान बैंक ने नए ग्राहक-आधार में 46.5% की वृद्धि दर्ज की

त्वरित ऋण-प्रदायगी

ऋण-प्रदायगी के नए मॉडल के परिणामस्वरूप समग्रतः कार्रवाई अवधि सुधरकर 11 दिन हो गई और नए / त्वरित ऋण-प्रदायगी उत्पादों के लिए यह 5 दिन रही

व्यवसाय समर्थकारक और प्रक्रियागत सुधार

- राष्ट्रीय स्तर के 44 प्रतिष्ठित मूल उपकरण विनिर्माताओं और 5 उद्योग संघों के साथ गठजोड़
- सिटी यूनियन बैंक व येस बैंक के साथ कार्यशील पूंजी प्लेटफॉर्म आरम्भ किया गया
- वित्त वर्ष 2020 के दौरान शुरू किए गए 13 नए उत्पादों ने कुल मंजूरियों में ₹926 करोड़ और कुल संवितरणों में ₹652 करोड़ का योगदान किया
- ऋण-प्रदायगी मॉडल को पुनर्संरचित किया गया
- स्मार्ट मूल्यांकन टूल को उन्नत बनाया गया, ताकि वह उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और बेहतर रूप में एकीकृत हो सके

कोविड का प्रतिकार

कोविड 19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए एमएसएमई हेतु पहलकदमियाँ

- 30 जून, 2020 तक 3,252 सावधि ऋण ग्राहकों ने कोविड 19 संबंधी उपायों के अंतर्गत राहत प्राप्त की
- 199 कार्यशील पूंजी खातों में प्राप्य ब्याज राशि की वसूली अगस्त 2020 तक के लिए आस्थगित की गयी
- आरम्भ की गयीं नयी योजनाएँ -
  - कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में ₹1.5 करोड़ तक की सहायता हेतु 'लिक्विड' योजना
  - एमएसएमई इकाइयों को 5% पर पूंजीगत-व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए 'सेफ' योजना, जिसकी कार्रवाई अवधि 48 घंटे है
  - सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों से मिले आदेशों की पूर्ति के लिए तत्काल कार्यशील पूंजी सहायता हेतु 'सेफ प्लस' योजना
  - स्माइल के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के पूंजीगत-व्यय वित्तीयन संबंधी जरूरतों के लिए विशेष सुविधा
  - कार्यशील पूंजी योजना के अंतर्गत आकस्मिक तदर्थ सीमा और प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत आकस्मिक सावधि ऋण

प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत संकेंद्रित पहल - दीर्घकालिक विकास

एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता का वित्तपोषण, जीईएफ़ द्वारा वित्तपोषित विश्व बैंक की परियोजना:

- 26 उद्योग समूहों में कार्यान्वित
- ऋण 'आद्यंत ऊर्जा दक्षता (4ई) योजना' के अंतर्गत दिए जाते हैं
- विश्व बैंक ने 'अत्यधिक संतोषप्रद' होने की रेटिंग दी

ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम साझेदारी की सुविधा

- लगभग ₹251 करोड़ की समूह-निधि वाली गारंटी निधि और ₹41 करोड़ की तकनीकी सहायता
- जीईएफ़, सीटीएफ़ और विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजना, जिसे ईईएसएल और सिडबी ने कार्यान्वित किया
- 10 ईएससीओ को दिए गए ऋणों के प्रति बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ₹113 करोड़ की ऋण राशि की गारंटी दी गई
- समाहित परियोजनाएँ 14 से बढ़कर 24 हो गईं और गारंटीकृत ऋण राशि दुगनी होकर ₹42 करोड़ से ₹84 करोड़ हो गई

एमओईएफ, भारत सरकार से नामांकन के फलस्वरूप बैंक जीसीएफ की "राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था" बन गया है

टिफाक-सिडबी (सृजन) योजना

- ₹25.88 करोड़ मंजूर किए गए
- नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित 30 परियोजनाओं को सहायता दी

निधियों की निधि का परिचालन

अभिनव और विप्लवकारी व्यवसाय मॉडलों के लिए सहायता

बैंक निधियों के लिए निधि कार्यक्रमों जैसे- स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए निधियों की निधि (एफएफएस), ऐस्पायर निधि (एएफ), आखिल भारतीय निधियाँ, क्षेत्रीय निधियाँ, एमएसएमई-आरसीएफ और इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ) का परिचालन कर रहा है, जिनमें व्यवसाय-चक्र के विभिन्न चरणों जैसे बीज चरण "ए", प्रारंभिक चरण आदि में कंपनियों में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में योगदान किया जाता है।

अखिल भारतीय निधियों, क्षेत्रीय निधियों, एमएसएमई-आरसीएफ और आईएएफ के अंतर्गत प्रतिबद्धताएँ विनिवेश / निकास के चरण में हैं, जबकि एफएफएस और एएफ के अंतर्गत प्रतिबद्धताएँ जारी हैं।

सक्रिय निधियों का संक्षिप्त विवरण

स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए निधियों की निधि (डीपीआईआईटी)

ऐस्पायर निधि

ऐसी उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में योगदान किया गया, जो ग्रामीण और कृषि उद्योगों में स्टार्ट-अप और शुरुआती चरण के उद्यमों पर केंद्रित हैं

31 मार्च, 2020 तक, बैंक ने पाँच एआईएफ को ₹47.50 करोड़ की प्रतिबद्धताएँ की हैं

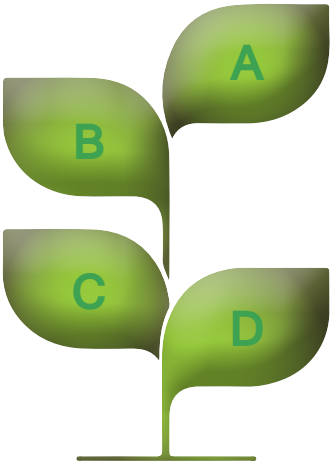

₹310 करोड़ की समूह-निधि

31 मार्च, 2020 तक आहरित हुए ₹27.70 करोड़ से 49 एमएसएमई इकाइयों (27 ग्रामीण-कृषि कंपनियों) में निवेश किया गया

एमएसएमई पर प्रभाव - निधियों की निधि

- ☑ 31 मार्च, 2020 तक 140 एआईएफ को ₹6,154.71 करोड़ की संचयी मंजूरी और ₹2,848.13 करोड़ के संवितरण कर सहायता प्रदान की गई है
- ☑ एफएफएस के तहत लगभग 30,000 रोजगार सृजित

जोखिम प्रबंध का सुदृढ़ीकरण

3 नई उत्पादों / योजनाओं के लिए स्कोर कार्ड प्रारंभ किया गया

प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत ₹7.5 करोड़ से अधिक के एक्स्पोज़र के लिए एसएमई रेटिंग प्रारंभ की गयी

वर्तमान जोखिम प्रबंध ढाँचे के मूल्यांकन और कमियों के अध्ययन के लिए बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया और सिफ़ारिशें लागू की जा रही हैं

आईटी / साइबर जोखिमों की निरंतर निगरानी और उनके शमन के लिए सीएसओसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई

बीसीएम, साइबर और आईटी सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

अल्प वित्त / उपेक्षित मध्यवर्ती उद्यम - *प्रयास*

इसका लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कम लागत वाली पूँजी के ज़रिये उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार करना है, ताकि वे जीवनक्षम बन सकें

साझेदारी मॉडल के जरिये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि निदर्शी प्रभाव पड़े

8 वित्तीय भागीदार संस्थाओं और 2 गैर-वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ साझेदारी की

31 मार्च, 2020 तक 14,000 सूक्ष्म-उद्यमियों / उधारकर्ताओं को कुल ₹161.11 करोड़ की सहायता मंजूर की गई

एमएसएमई पर प्रभाव - प्रयास

- ☑ प्रयास योजना ने सूक्ष्म उद्यमियों को अपने व्यवसाय की स्तरोन्नति करने / आजीविका के अवसरों में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी मदद की
- ☑ 31 मार्च, 2020 तक 11,000 सूक्ष्म उद्यमियों को ₹126 करोड़ संवितरित किए गए
- ☑ समस्त लाभार्थियों में महिला और ग्रामीण लाभार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 74% और 88% है

संरचनात्मक पहलकदमियाँ

सूचना की विषमता दूर करने और नीति-निर्माताओं के मार्गदर्शन के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न पहलकदमियाँ की हैं

एमएसएमई पल्स सिडबी और ट्रांसयूनियन सिबिल की एक पहल है, जो 50 लाख से अधिक ऋणों का उपयोग करने वाली एमएसएमई इकाइयों के आधार पर एमएसएमई इकाइयों की स्थिति का आकलन करता है। मार्च 2020 तक अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और तमिल में इसके 8 संस्करण जारी हुए हैं

क्रिसिडेक्स सिडबी और क्रिसिल का एक संयुक्त सूचना उत्पाद है। यह एक संवेदी सूचकांक है, जो किसी सर्वेक्षणाधीन तिमाही में लगभग 1100 एमएसई के गुणात्मक सर्वेक्षण और उसकी आगामी तिमाही की संभावनाओं पर आधारित होता है। मार्च 2020 तक इसके 9 संस्करण जारी हुए हैं।

माइक्रोफाइनेंस पल्स सिडबी और इक्विफैक्स की एक संयुक्त पहल है, जो अल्प वित्त क्षेत्र की ऋण संबंधी प्रवृत्तियाँ और अन्य रुझानों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मार्च 2020 तक इसके 4 संस्करण जारी किए गए हैं

सिडबी राष्ट्रीय माइक्रोफ़ाइनेंस कांग्रेस : अल्प वित्त क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं और हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से द्वितीय सिडबी राष्ट्रीय माइक्रोफाइनेंस कांग्रेस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक संगठनों के 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया

चिह्नित उद्योग क्षेत्रों, फिनटेक वित्तीयन के क्षेत्रों, आदि से संबंधित ज्ञान उत्पाद लाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठजोड़ के प्रयास जारी हैं

डिजिटल वित्तीयन संबंधी पहलकदमियाँ

उद्यमीमित्र पोर्टल : एमएसएमई आकांक्षियों के लिए सुगमता से ऋण तक पहुँचने का एक व्यापक डिजिटल मंच

- 140 ऋणदाता
- 1.3 लाख से अधिक शाखाओं का तंत्र

- कुल पंजीकरण : 5.23 लाख
- ऑनलाइन ऋण आवेदन : 1.38 लाख
- ₹1,377 करोड़ की राशि के 7,238 ऋणों की ऑनलाइन मंजूरी

- सीएससी और आरएसईटीआई के साथ संस्थागत गठजोड़ स्थापित किए गए
- आरएसईटीआई को 39,089 अनुरोध मिले, जिनमें से उन्होंने 10,588 अनुरोधों का जवाब दिया
- 5,996 पीएमकेवीवाई केंद्रों और 463 पीएमकेके केंद्रों की मैपिंग करते हुए एनएसडीसी से गठजोड़ किया गया

- समृद्धि, जो आभासी सहायक (चैटबॉट) है, उसने 3.49 लाख प्रश्नों का जवाब दिया
- बैंकेबिलिटी किट के 5.8 लाख डाउनलोड हुए
- 1.5 लाख इच्छुक पार्टियों ने 325 परियोजना प्रोफ़ाइलें देखीं
- 78,957 सीएससी ने 28,184 आवेदकों और 3,104 आवेदनों के पंजीकरण में मदद की

पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पोर्टल पर डिजिटल-संपर्कविहीन खुदरा उत्पाद जैसे वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, आदि प्रारंभ कर दिए

अपनी पहुँच और ऋणों के प्रकार के मामले में यह सबसे बड़ा फिनटेक मंच बन कर उभरा है

31 मार्च, 2020 तक, 3.03 लाख एमएसएमई इकाइयों ने ऋणदाताओं से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की थी, जिसमें से 2.06 लाख एमएसएमई इकाइयों ने अंतिम मंजूरी प्राप्त की

सुगमकार की भूमिका

भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाओं जैसे सीएलसीएसएस, टफ़्स, आईडीएलएसएस, एफपीटफ़्स और टेकअप के क्रियान्वयन के लिए बैंक को नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान परिचालन :

691 एमएसएमई इकाइयों को ₹60.90 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई

संचयी रूप से, ₹3,427.08 करोड़ की सब्सिडी 40,692 एमएसएमई इकाइयों को जारी की गई

टफ़्स के अंतर्गत सिडबी से प्रत्यक्ष सहायता-प्राप्त इकाइयों के 212 सब्सिडी दावों के प्रति ₹ 2.78 करोड़ और सहयोजित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं से संबंधित 489 सब्सिडी दावों के प्रति ₹3.68 करोड़ जारी किए गए

टेकअप के अंतर्गत ₹54.44 करोड़ के 691 दावे जारी किए गए। टेकअप योजना अब सीएलसीएस - टीयूएस योजना में सम्मिलित हो गई है

एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत सीएफसी और औद्योगिक मूलभूत संरचना के ऐसे 60 प्रस्ताव एनएलएससी ने मंजूर कर दिए, जिनका मूल्यांकन बैंक ने किया था। 12 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एनएलएससी को भेजे गए

एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में रूपायित सीएलसीएस-टीयूएस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष अर्थात् 2017-18 से 2019-20 तक सीएलसीएसएस घटक जारी रखने की घोषणा की

एमएसएमई के वर्द्धित बकाया ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) -2018

- "एमएसएमई इकाइयों के वर्द्धित बकाया ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018" हेतु कार्यान्वयन एजेंसी
- 31 मार्च, 2020 तक, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹625 करोड़ में से 59 पात्र संस्थाओं के ₹604.69 करोड़ के दावों का निपटान किया गया
- इस योजना से 9.58 लाख एमएसएमई इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं।

आंशिक ऋण गारंटी योजना

- एनबीएफसी / एचएफसी के ऊँची रेटिंग वाले आस्ति-समूहों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी जाने वाली गारंटी
- बैंक को प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और संव्यवहारों का रिकॉर्ड रखने, तथा गारंटी हेडरूम के निर्धारण, दावों की जाँच और वसूली की निगरानी करने का काम सौंपा गया है

एमएसएमई *सक्षम*

- एमएसएमई को ऋण-सक्षम बनाने के लिए सिडबी और ट्रांसयूनियन सिबिल की संयुक्त ऋण जागरूकता पहल
- डिजिटल मल्टी-चैनल सामग्री युक्त पोर्टल, जिसमें एमएसएमई को शिक्षित करने, उनसे बातचीत करने और उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न संपर्क-बिंदु हैं
- सिबिल रैंक और क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुँचने में सक्षम बनाता है
- 30 जुलाई, 2020 को पोर्टल आरंभ किया गया

अध्याय 3 ▸ संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ

बैंक की संवर्द्धनशील एवं विकासपरक गतिविधियाँ, संपर्क, संवाद, सुरक्षा, संप्रेषण (4स) के चार मार्गदर्शी विषयों के अंतर्गत चलाई जाती हैं, ताकि एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न गैर-वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

संपर्क - "एमएसएमई एवं उद्यमियों के साथ संपर्क" का महत्त्व दर्शाता है

स्वावलंबन सूचना शृंखला	• उद्यमिता, उद्यमों की स्थापना / उन्नति तथा उनके विकास-क्रम के संबंध में जानकारी देने वाले 4 खंड और एक सारसंग्रह छह स्थानीय भाषाओं में जारी किए गए • उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय साक्षरता फ़िल्में, रेडियो विज्ञापन-गीत, उद्यमिता स्तुतिगान तथा उद्यमिता प्रतीक जारी किए गए • सिडबी यू-ट्यूब चैनल "SIDBIOfficial" पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत 155 सूचनापरक वीडियो उपलब्ध हैं • प्रकाशन / ऑनलाइन सामग्रियाँ परिचालित की गईं, जिनसे 25,000 से अधिक संभावित / मौजूदा उद्यमी लाभान्वित हुए
स्वावलंबन भित्ति-चित्र और क्लब	• युवाओं को उद्यमिता के बारे में शिक्षित करने के लिए आठ राज्यों के 118 कॉलेजों में स्वावलंबन भित्तिचित्रों का निर्माण किया गया • 15 स्वावलंबन क्लबों की स्थापना की गई, जिनमें प्रति क्लब औसत 35 सदस्य हैं
स्वावलंबन बाज़ार+	• इन बाज़ारों के रूप में सूक्ष्म उद्यमियों और स्थानीय शिल्पकारों के कौशल और उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए मंच उपलब्ध कराया गया तथा ऋण, डिज़ाइन, बाज़ार संबंध, वित्तीय साक्षरता, आदि उपलब्ध कराए गए • इन्हें नौ राज्यों के 12 शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें 600 से अधिक शिल्पकारों / सूक्ष्म-उद्यमियों ने भागीदारी की और इनमें 3.25 लाख आगंतुक आए • प्रत्येक मेले में औसतन ₹13.28 लाख की बिक्री दर्ज की गई
उद्यम संज्ञान (निदर्शन दौरे)	• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मध्यम और बड़े उद्योगों में निदर्शन दौरे • विव 2020 के दौरान, ऐसे 22 दौरे आयोजित किए गए, जिनसे 573 एमएसएमई इकाइयाँ लाभान्वित हुईं
राज्य संपर्क कार्यक्रम	• इसका लक्ष्य एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़ने को बढ़ावा देना और एक राज्य की अच्छी प्रथाओं को अन्य राज्यों के साथ साझा करना • यह कार्यक्रम 10 राज्यों में आयोजित किया गया और इनमें 2,106 हितधारकों ने भागीदारी की • 13 राज्यों में परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू) की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई

संवाद - एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए पारस्परिक विमर्श

- सिडबी और सरकारी योजनाओं के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए हौज-खास मेट्रो स्टेशन को 10 साल की अवधि के लिए अंगीकृत किया गया
- पृच्छाओं (पूछताछ) के जवाब के लिए स्टेशन पर दो कियोस्क स्थापित की गईं
- स्टेशन पर औसतन 1 लाख से अधिक लोगों का आवागमन

- बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर 170 अधिकारियों ने 456 सड़क किनारे रेहड़ी-खोमचे लगाने वालों विक्रेताओं, सूक्ष्म इकाई धारकों से भेंट की, ताकि उनकी दैनंदिन समस्याएँ एवं चुनौतियाँ समझी जा सकें
- लगभग 110 सक्षम अनुकरणीय उद्यमियों की पहचान की गई और उनमें से 35 को अनुकरणीय उद्यमी पहल के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई

- सिडबी की महिला उद्यमी सशक्तीकरण परियोजना (एमयूएसपी) के तहत सहायता-प्राप्त महिला सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शित करने, व्यवसाय-नेटवर्क स्थापित करने व नए क्रय-आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2-दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया
- एमयूएसपी के तहत सहायता-प्राप्त 10,000 महिला सूक्ष्म उद्यमियों में से 700 ने इसमें प्रतिभागिता की
- स्वावलंबन उत्सव के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री से सराहना संदेश प्राप्त हुआ

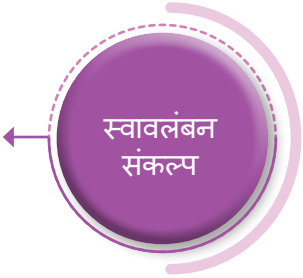

- अ.जा. / अ.ज.जा. के सभावित उद्यमियों को मुख्यधारा में लाने के लिए डीआईसीसीआई के माध्यम से 30 अखिल भारतीय संकल्प कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई
- 9 संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं

सुरक्षा - एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए एक समर्थकारी परिवेश का निर्माण

स्वावलंबन संपर्क केंद्र (एससीके)

- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में स्वावलंबन संपर्क केंद्रों (एससीके) की स्थापना की गई, ताकि आकांक्षी उद्यमियों को आरंभ से अंत तक सहायता दी जा सके
- कार्यक्रम के तहत 100 एससीके की स्थापना की गई
- 4,426 आकांक्षियों का प्रारंभिक विवरण (रूपरेखा) और 3,158 आकांक्षियों का उन्नत विवरण (रूपरेखा) तैयार किया गया
- 49 आकांक्षियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब तक 39 उद्यमों की स्थापना की गई

स्वावलंबन सिलाई स्कूल

- उषा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में अनुकरणीय गृह-उद्यमी तैयार करना और प्रोत्साहित करना
- 5 राज्यों के 10 ज़िलों में 1,000 सिलाई स्कूलों की स्थापना, जिनसे 1,000 ग्रामीण महिलाएँ लाभान्वित हुई, इनमें 59% महिलाएँ गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी से और 45% महिलाएँ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हैं
- प्रत्येक गृह-उद्यमी ने 3 अन्य महिलाओं को नामांकित किया, इसके फलस्वरूप मार्च, 2020 तक कुल 3,273 नामांकन हुए
- दूसरे चरण में 3 राज्यों में 700 और स्कूलों की योजना बनाई गई है

सह-कार्य स्थल

- इंक्यूस्पेज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में बैंक के दिल्ली कार्यालय परिसर में "वर्कस्पेज़" प्रारंभ किया गया, जिससे 39 उद्यम लाभान्वित हुए
- बीकेसी मुंबई में एक अन्य सह-कार्य स्थल की स्थापना की जा रही है

उद्यम ज्ञानशाला [आईआईएम, लखनऊ में प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी)]

- "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए" 11 दिन की कार्यशाला रूपायित की गई
- इस कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है, इनसे विव 2020 में 34 एमएसई लाभान्वित हुए

ईयू-स्विच एशिया बाँस परियोजना

- इसका लक्ष्य बाँस आधारित उद्यमों का संवर्द्धन करना और हरित रोज़गार पैदा करना है
- 5 उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के 9 राज्यों में लागू किया गया
- बाँस आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए, संचयी रूप से 2,734 कारीगरों का मार्गदर्शन किया गया
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, परियोजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक इकाइयों की स्थापना की गई या उन्हें उन्नत बनाया गया
- मेघालय में नए / संभावी उद्यमियों के उद्यमिता उत्साह को साकार बनाने के लिए स्वावलंबन लैब की स्थापना के लिए सहायता दी गई

संप्रेषण - नीति निर्माताओं और एमएसएमई उद्यमियों के साथ रचनात्मक संवाद

सिडबी-ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार का द्वितीय संस्करण

- पुरस्कार के द्वितीय संस्करण के लिए **13,000** से अधिक पंजीकरण हुए और **500** से भी अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की
- पुरस्कार के अंतर्गत, प्रत्येक विजेता के लिए मार्गदर्शी सहायता और प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) में भागीदारी सुलभ कराई गई
- यह पुरस्कार एक विशिष्ट राष्ट्रीय आयोजन के रूप में उभरा, इसमें राष्ट्रीय भागीदारों की संख्या चार से बढ़कर आठ हो गई

पुरस्कार एवं मान्यता

बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए **"बिज़नेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट"** के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नैगम छवि अभिवर्द्धन

प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय टेलीविज़न और रेडियो में नियमित और लगातार कवरेज के साथ एमएसएमई पारितंत्र में बैंक के बारे में प्रचार-प्रसार में पर्याप्त वृद्धि की गई।

कोविड का प्रतिकार

आजीविका के लिए सहायता

निम्न कार्यों के लिए 9 राज्यों में कार्यरत 11 एजेंसियों / गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की :

60,000 से अधिक **मास्कों** का वितरण

2,000 से अधिक **परिवारों** को कच्चे राशन (भोजन) और सैनिटाइजर का वितरण

लॉकडाउन की समस्याओं का सामना करने के लिए **100** **आजीविका उद्यमियों** को सहायता

5,000 **प्रवासी मजदूरों, दैनिक वेतनभोगियों** को खाद्य वितरण में मदद के लिए सहायता

मास्क बनाने के लिए **45** **स्वसहायता समूहों** और **65** **गृह-उद्यमियों** को सहायता

पूर्वोत्तर क्षेत्र और तमिलनाडु में **900** से अधिक **आजीविका विक्रेताओं** के लिए सुरक्षा कवच

बैंक ने कोविड महामारी के विरुद्ध जारी संघर्ष के समर्थन के लिए "आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹15 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹5 करोड़ की राशि दान की।

निर्धनतम राज्य समावेशी संवृद्धि (पीएसआईजी) कार्यक्रम

डीएफ़आईडी, यूके के माध्यम से यूकेऐड द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक निर्धनता वाले राज्यों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं की आय और रोज़गार के अवसरों में अभिवृद्धि करना था। यह कार्यक्रम 31 मार्च 2020 को संपन्न हो गया है।

एमएसएमई पर प्रभाव - संवर्द्धन एवं विकास

- ☑ 30 संवर्द्धनशील और विकासपरक गतिविधियों के माध्यम से 5 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए और इसमें आर्थिक रूप से गरीब राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया
- ☑ वित्तवर्ष 2020 में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित पेयजल, आदि के क्षेत्र में 30 से अधिक सीएसआर गतिविधियाँ की गईं

सहायक / सहयोगी संस्थाएँ
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावकारी

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) (1999)

- यह निवेश प्रबंध कंपनी है, जो वर्तमान में आठ निधियों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है और इसकी आहरण-योग्य समूह-निधि ₹1,754.24 करोड़ है
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, एसवीसीएल ने फ़िनटेक, उपभोक्ता-केंद्रित नवोन्मेषी उत्पादों, हरित प्रौद्योगिकी और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ₹500 करोड़ की लक्ष्य समूह-निधि वाली नवीन होराइजन निधि (एनएचएफ़) की स्थापना की
- निर्यात-उन्मुख इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ₹250 करोड़ की समूह-निधि वाली उभरते सितारे निधि की स्थापना प्रक्रियाधीन है

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) (2015)

- मुद्रा ने वित्तवर्ष 2020 के दौरान ₹4,000 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की और 31 मार्च, 2020 को इसका बकाया संविभाग ₹9,090 करोड़ था
- 31 मार्च, 2020 तक मुद्रा द्वारा संचयी मंज़ूरियाँ और संवितरण क्रमश: ₹27,141 करोड़ और ₹25,495 करोड़ रहे

उड़ान ब्रांड के रूप में कार्यरत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई (सीजीटीएमएसई) (2000)

- ₹2 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं के संबंध में एमएसई के लिए ऋण गारंटी योजना
- वित्तवर्ष 2020 के दौरान उपलब्धियाँ:

i. वर्षानुवर्ष 52% की वृद्धि के साथ, अनुमोदित गारंटियाँ बढ़कर ₹45,852 करोड़ हो गई

ii. वर्षानुवर्ष 94% की वृद्धि के साथ, अनुमोदित गारंटियों की संख्या, वर्ष 2019 के 4.36 लाख से बढ़कर वित्तवर्ष 2020 में 8.47 लाख हो गई

रिसेवेबल एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (2016)

- यह एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसेवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म (ट्रेड्स) परिचालित करने वाला सिडबी-एनएसई का संयुक्त उद्यम है
- 31 मार्च, 2020 को इसके पास 1,787 एमएसएमई विक्रेता, 489 क्रेता (102 सीपीएसयू सहित) और 35 वित्तपोषक (फाइनेंसर) पंजीकृत थे
- 31 मार्च, 2020 को आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने संचयी रूप से ₹3,816.39 करोड़ के सकल मूल्य के 94,342 से अधिक बीजकों के प्रति फ़ैक्टरिंग (वित्तपोषण) की

एमएसएमई पर प्रभाव - सहायक / सहयोगी संस्थाएँ

1. सीजीटीएमएसई ने ₹2.21 लाख करोड़ से अधिक राशि के ऋणों के प्रति 43.07 लाख गारंटियाँ मंज़ूर की हैं और 2.59 लाख दावों के प्रति संचयी आधार पर ₹6,370.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया है

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूट) (2005)

- भारत की पहली एमएसएमई-केंद्रित रेटिंग एजेंसी, जो अब एक पूर्ण-सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है
- एक्यूट ने 31 मार्च, 2020 तक 50,000 से अधिक एसएमई रेटिंग और 8,000 से अधिक बैंक ऋण रेटिंग पूरी की हैं

इंडिया एसएमई ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (2008)

- 31 मार्च, 2020 तक ₹402.18 करोड़ की आस्तियाँ इसके प्रबंधाधीन हैं

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (2005)

- आईएसटीएसएल एमएसएमई इकाइयों के लिए ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करती है
- आईएसटीएसएल प्रौद्योगिकी विकल्प, मैच मेकिंग, वित्त समूहन (सिंडिकेशन) और व्यावसायिक सहयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है

ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड
पीएसबीलोन्सइन59मिनट्स

- पहुँच और प्रदत्त ऋणों के संदर्भ में सबसे बड़ा फिनटेक प्लैटफ़ॉर्म
- 31 मार्च 2019 तक 50,706 एमएसएमई इकाइयों की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक 3.03 लाख एमएसएमई इकाइयों ने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले ऋणदाताओं से सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त की है
- 31 मार्च, 2019 तक 27,983 एमएसएमई इकाइयों की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक 2.06 लाख एमएसएमई इकाइयों को अंतिम मंज़ूरी मिल गई है

2. सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त इकाइयों ने 127 लाख रोज़गार सृजित किए हैं और निर्यात के प्रति ₹14,648 करोड़ का योगदान किया है
3. आरएक्सआईएल ने एमएसएमई इकाइयों को उनकी ब्याज लागत 5% तक कम करने में मदद की है - प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे कम ब्याजदर @ 6.60% प्रतिवर्ष रही

अध्याय 4 ▸ प्रबंधतंत्र और नैगम अभिशासन

बैंक ने नैतिकता के अनुकरणीय मानक कायम रखते हुए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैगम अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाई हैं और उनका पालन किया है।

निदेशक-मंडल का संघटन

सिडबी अधिनियम में 15 निदेशकों वाले निदेशक-मंडल का प्रावधान है

बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2019 को लखनऊ में संपन्न हुई।

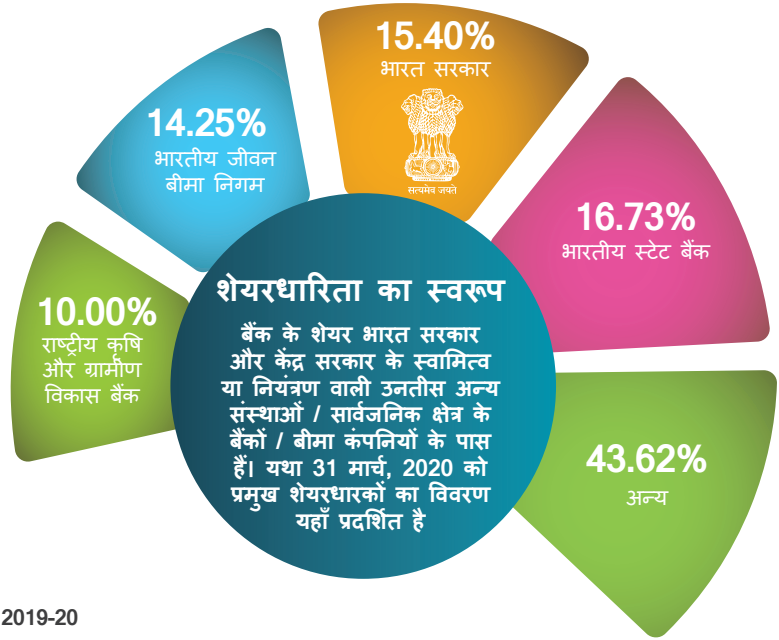

जोखिम प्रबंध

जोखिम प्रबंध संरचना में विभिन्न नीतियाँ, सांगठनिक ढाँचा, आईटी प्रणालियाँ, निर्धारण, मापन, शमन और विभिन्न जोखिमों की निगरानी शामिल हैं।

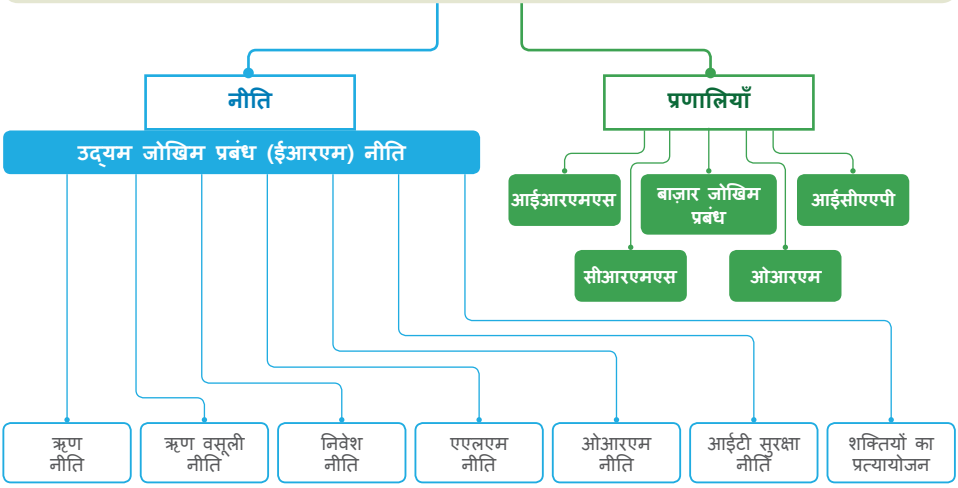

विलुप्त डेटा प्रग्रहण, प्रमुख जोखिम संकेतक तथा जोखिम एवं नियंत्रण के स्व-मूल्यांकन के लिए एक व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकक (कोर) प्रणाली क्रियान्वित की गई।

आंतरिक समितियाँ (वित्तवर्ष के दौरान बैठकों की संख्या)

- उद्यम जोखिम प्रबंध समिति (4 बैठकें)
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम - आंतरिक परिवाद समिति (कोई शिकायत नहीं)
- जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति (3 बैठकें)
- निवेश समिति (37 बैठकें)
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध संचालन समिति (3 बैठकें)
- आस्ति देयता प्रबंध समिति (34 बैठकें)

गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध

नई पहलकदमियाँ

- गैर-निष्पादक आस्ति संविभाग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए 7 विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ और 1 वसूली कक्ष स्थापित
- ऋण वसूली नीति को और अधिक व्यवहारिक, दक्ष और परिणामोन्मुखी बनाया गया

परिचालन संबंधी प्रयास

- निदेशक-मंडल स्तर की आरआरसी - ₹3 करोड़ या उससे अधिक राशि की सभी गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा
- प्र. का. एवं परिचालन कार्यालयों के बीच आवधिक विचार विमर्श
- भारतीय रिज़र्व बैंक के एमएसएमई के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास संबंधी ढाँचे के तहत गठित क्षेत्रीय स्तर की समितियाँ
- विशेष उल्लेखनीय (एसएमए) खातों की पाक्षिक समीक्षा के लिए दबावग्रस्त आस्ति निगरानी समिति
- सिस्टम स्वचालन और दैनंदिन सचेतक संदेशों (अलर्ट) का आरंभ

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

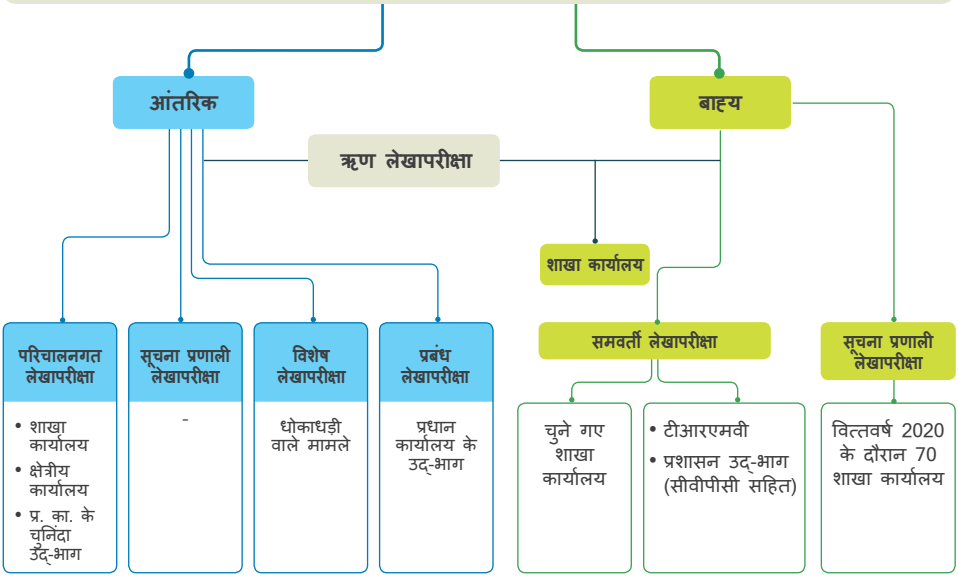

मानव संसाधन

मानव संसाधन संबंधी गतिविधियाँ

- बैंक के निदेशक मंडल और उसकी समितियों के स्वतंत्र मूल्यांकन / समीक्षा के लिए सलाहकार संस्था की सेवाएँ ली गई
- डेलॉएट टुशे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी द्वारा जन-शक्ति का विश्लेषण किया गया और वह निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया
- प्रतिस्पर्धी एवं लक्ष्योन्मुख कार्य-संस्कृति सुकर बनाने के लिए कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली क्रियान्वित की गई
- कोविड-19 की वैश्विक महामारी और अनंतर लॉकडाउन के दौरान, बैंक का अबाध परिचालन सुनिश्चित किया गया
- ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से यौन-उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया गया
- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के डिजिटल प्रबंध के लिए "टीम" का प्रवर्तन किया गया
- कर्मचारी अनुकूल प्रयास
  - ▸ देर रात तक काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था
  - ▸ सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की नक़दी-मुक्त व्यवस्था
  - ▸ जन्मदिन के अवसर पर स्टाफ़-सदस्यों को पौधों का उपहार

मानव संसाधन संख्या (31 मार्च, 2020)

- कुल स्टाफ़ - 1,048
- अधिकारी - 916 अधिकारी
- श्रेणी III के कर्मचारी - 93
- अधीनस्थ कर्मचारी - 39
- अनुसूचित जाति - 182, अनुसूचित जनजाति - 79, अन्य पिछड़ा वर्ग - 206
- भूतपूर्व सैनिक - 5, दिव्यांगजन - 31, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक - 1
- महिला कर्मचारी - 240 (23%)

प्रशिक्षण एवं विकास

- आंतरिक प्रशिक्षणों तथा देश के प्रख्यात प्रशिक्षण / अकादमिक संस्थाओं में 1,271 नामांकन
  - ▸ आंतरिक प्रशिक्षणों में नामांकन - 1,201
  - ▸ प्रख्यात प्रशिक्षण / अकादमिक संस्थाओं में - 70
  - ▸ महिलाएँ - 272
  - ▸ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - 600
- प्रमुख आंतरिक कार्यक्रम
  - ▸ ईएलएससी और शाखा कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विपणन कार्यक्रम
  - ▸ उन्नत ऋण मूल्यांकन और वसूली संबंधी आयाम विषय पर कार्यक्रम
  - ▸ व्यवसाय सातत्य प्रबंध, साइबर सुरक्षा एवं आईटी सुरक्षा आदि विषय पर जागरूकता कार्यक्रम
  - ▸ 95 अधिकारियों के लिए कार्यशील पूँजी प्रबंध विषय पर 3 कार्यक्रम
  - ▸ कुल 126 अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम
  - ▸ ई-लर्निंग पोर्टल पर 3 नए मॉड्यूलों का प्रवर्तन

सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- प्रधान कार्यालय पर सतर्कता दल
- अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी
- क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी

समितियाँ

- क्षेत्रीय कार्यालयों में निवारक सतर्कता समितियाँ
- प्रधान कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता समिति
- सतर्कता संबंधी आंतरिक सलाहकार समिति

परिचालनगत ढाँचा

- मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा
- सीटीईओ-स्वरूप के निरीक्षणों के माध्यम से निविदा प्रक्रिया की आवधिक चौकसी
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा तिमाही आधार पर सतर्कता कार्यों की समीक्षा
- सतर्कता संबंधी कामकाज का स्वचालन / डिजिटलीकरण
- सर्तकता के बारे में कार्यशालाओं, व्याख्यानों, सुग्राहिता कार्यक्रमों का आयोजन

सूचना प्रौद्योगिकी

- अल्पवित्त संस्थाओं के ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए वेबपोर्टल का आरंभ
- प्रमुख व्यवसाय अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) और "स्विफ्ट" के साथ एकीकृत विदेशी ऋण-व्यवस्था के परिचालनों और विप्रेषणों की आद्योपांत स्वचालित संसाधन प्रणाली का क्रियान्वन
- अतिरिक्त विशिष्टताओं के साथ ऑनलाइन सावधि जमा पोर्टल का पुनःप्रवर्तन
- कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान, स्काइप फ़ॉर बिज़नेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम, डीएमएस जैसे स्वचालन साधनों का प्रभावी नियोजन
- अपने साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का कार्यान्वयन आरंभ
- डेटा केंद्रों को पुन: तीन वर्ष की अवधि के लिए आईएसएमएस-आईएसओ / आईईसी 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त हुआ
- नेटवर्क वैंडविथ के प्रभावी उपयोग के लिए सभी स्थानों पर एसडी-वैन का क्रियान्वयन किया गया

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की श्रेणी में 'क' क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त

वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार

विभिन्न कार्यालयों में 88 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार क्रमशः 93%, 91% और 73% रहा

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी टिप्पणियाँ क्रमशः 83%, 76% और 52% रहीं

हिंदी प्रत्रिका 'संकल्प' के 92 अंक प्रकाशित

44 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित

तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक सॉफ्टवेयर का प्रवर्तन

सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय स्थापित है और उसके बजट का सदुपयोग हिंदी पुस्तकों की खरीदारी के लिए किया गया

राजभाषा निरीक्षण के लिए 44 कार्यालयों और 8 उद्-भागों का दौरा किया गया

15वीं अखिल भारतीय अंतरबैंक सिडबी हिंदी निबंध प्रतियोगिता और अखिल भारतीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन आयोजित

द्वितीय अखिल भारतीय सिडबी ऑनलाइन राजभाषा प्रश्नमंच प्रतियोगिता आयोजित की गई

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

- वित्तवर्ष 2020 के दौरान, सूचना के अधिकार से संबंधित 254 आवेदन प्राप्त हुए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी आवेदन निपटाए गए
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को 23 अपीलें प्रस्तुत की गईं, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के प्रति कोई भी अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई

सिडबी
www.sidbi.in

प्रधान कार्यालय
सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.)
फोन नंबर : 0522-2288546-49, 0522-4261600, 4259700
फैक्स नंबर : 0522-2288459

शाखा कार्यालय

यथा जुलाई 31, 2020

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद शाखा कार्यालय, अहमदाबाद ईएलएससी, अहमदाबाद एसएआरबी, चांगोदर शाखा कार्यालय, गांधीधाम शाखा कार्यालय, जामनगर आरआरओ, महेसाणा आरआरओ, मोरबी शाखा कार्यालय, ओढव शाखा कार्यालय, राजकोट शाखा कार्यालय, सूरत शाखा कार्यालय, वड़ोदरा शाखा कार्यालय, वटवा शाखा कार्यालय

• • •

चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

चंडीगढ़ शाखा कार्यालय, चंडीगढ़ एसएआरबी, जालंधर शाखा कार्यालय, जम्मू आरआरओ, लुधियाना शाखा कार्यालय, शिमला आरआरओ, यमुनानगर शाखा कार्यालय

• • •

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय I

चेन्नै एसएआरबी, कोयंबतुर शाखा कार्यालय, ईरोड शाखा कार्यालय, कोच्चि शाखा कार्यालय, मदुरै शाखा कार्यालय, तिरुपुर शाखा कार्यालय

• • •

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय II

अंबतुर शाखा कार्यालय, चेन्नै शाखा कार्यालय, कांचीपुरम शाखा कार्यालय, पुडुचेरी शाखा कार्यालय, चेन्नै ईएलएससी

• • •

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय

अगरतला शाखा कार्यालय, आइजॉल शाखा कार्यालय, दीमापुर शाखा कार्यालय, गंगटोक शाखा कार्यालय, गुवाहाटी शाखा कार्यालय, इम्फाल शाखा कार्यालय, ईटानगर शाखा कार्यालय, कोलकाता शाखा कार्यालय, शिलांग शाखा कार्यालय

• • •

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

बालानगर शाखा कार्यालय, बेंगलूरु शाखा कार्यालय, भुवनेश्वर शाखा कार्यालय, होसुर शाखा कार्यालय, हुबली आरआरओ, हैदराबाद शाखा कार्यालय, हैदराबाद ईएलएससी, हैदराबाद एसएआरबी, मैसूर शाखा कार्यालय, पीन्या शाखा कार्यालय, रायपुर शाखा कार्यालय, विजयवाड़ा शाखा कार्यालय, विशाखपट्टणम शाखा कार्यालय

• • •

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

भीलवाड़ा शाखा कार्यालय, भिवाड़ी शाखा कार्यालय, जयपुर शाखा कार्यालय, जोधपुर शाखा कार्यालय, किशनगढ़ शाखा कार्यालय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय, उदयपुर शाखा कार्यालय, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा कार्यालय

• • •

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

भोपाल शाखा कार्यालय, देहरादून शाखा कार्यालय, हरिद्वार शाखा कार्यालय, कानपुर शाखा कार्यालय, लखनऊ शाखा कार्यालय, लखनऊ ईएलएससी, लखनऊ एसएआरबी, पटना शाखा कार्यालय, प्रयागराज आरआरओ, रांची शाखा कार्यालय, रुद्रपुर शाखा कार्यालय, वाराणसी शाखा कार्यालय

• • •

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

बहादुरगढ़ शाखा कार्यालय, बल्लभगढ़ शाखा कार्यालय, फरीदाबाद शाखा कार्यालय, गुरुग्राम शाखा कार्यालय, कुंडली शाखा कार्यालय, नई दिल्ली शाखा कार्यालय, नई दिल्ली ईएलएससी, नई दिल्ली एसएआरबी, नोएडा शाखा कार्यालय

• • •

पुणे क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदनगर शाखा कार्यालय, औरंगाबाद शाखा कार्यालय, चिंचवड़ शाखा कार्यालय, इंदौर शाखा कार्यालय, कोल्हापुर शाखा कार्यालय, मुंबई ईएलएससी, मुंबई एसएआरबी, नागपुर शाखा कार्यालय, नासिक शाखा कार्यालय, पणजी शाखा कार्यालय, पुणे शाखा कार्यालय, ठाणे शाखा कार्यालय, वसई शाखा कार्यालय

• • •

आभार-ज्ञापन

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक-मंडल धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही, विश्व बैंक समूह; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका); डिपार्टमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफ़आइडी), यू.के.; क्रेडिटटांस्टाल्ट फर वीडराफबउ (केएफ़डब्ल्यू), जर्मनी; ड्यूश जेसेलशाफ्ट फ़र इंटरनेशनेल जुसमेनारबीट (जीआइजेड), जर्मनी; इंटरनेशनल फ़ंड फ़ॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम; एजेंस फ्रैंकेज डि डेवलपमेंट (एएफ़डी), फ्रांस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से प्राप्त संसाधन सहायता और तकनीकी सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बैंकों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, उद्योग संघों तथा एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास में लगे अन्य हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए निदेशक-मंडल उनकी भी सराहना करता है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों और निवेशकों को भी, उनसे प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में उनसे अनवरत सहायता की आकांक्षा करता है। वर्ष-पर्यंत, बैंक को उच्चतर विकास-पथ पर आगे बढ़ाने में प्रबल एवं अनवरत प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और समर्पण भावना से जुटे रहने वाले सिडबी के प्रत्येक स्तर के स्टाफ़-सदस्यों की सेवाओं के लिए निदेशक-मंडल उनकी प्रशंसा करता है।

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

WYATTPrism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)